तीन प्रति सत किया जाए। और क्या जो आप अधिनियम में संशोधन करना चाहते हैं वह इस मांग के अनुसार करने जा रहे हैं ?

Dr. K. L. Rao: No change will be made under that particular section.

श्री रामसेवक यादव : क्या मंत्री महोदय को यह जानकारी है कि बिजली कम्पनियों की दर में और जो सरकारी पावर स्टेशनों से उनको बिजली दी जाती है उसमें भारी अन्तर है, जिसका नतीजा यह होता है कि उपभोक्ताओं को भारी कठिनाई हो रही है और साथ ही साथ उपभोक्ताओं की सलाह भी नहीं ली जाती है। आज विभिन्न प्रदेशों और जिलों में बिजली की दरों में बड़ा भारी अन्तर है, और समानता नहीं है। क्या इन बातों पर भी ध्यान दिया जाएगा और देखा जाएगा कि उपभोक्ताओं का शोषण न हो और बिजली की दरें ज्यादा न बढ़ायी जाएं?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री श्यामधर मिश्र) : यह बात सही नहीं है कि सब जगह कम्पनियों की दर बहुत ज्यादा है। यह सही है कि कुछ जगहों पर बिजली कम्पनियों की दर अधिक है लेकिन उसका कारण ट्रांसमिशन लाइन्स की कमी आदि है। जहां दर ज्यादा है वहां बराबर जांच की जा रही है और सरकार को इलेक्ट्रिसिटी ऐक्ट के मातहत पावर है जिसके अनुसार दरों को कम किया भी जा रहा है।

श्री राम सहाय पाण्डेय: क्या यह सही नहीं है कि एक प्रदेश और दूसरे प्रदेश में बिजली की दर में अन्तर है ? यदि हां, तो इस अन्तर को दूर करने के लिये केन्द्रीय सरकार क्या करेगी ?

Dr. K. L. Rao: It is true that the rates are not uniform all over the States. With the establishment of the regional grids that we hope to build in the Fourth Plan we expect that there will be greater uniformity of rates within the States coming in the regions.

Jhuggis and Jhopris Removal Scheme

+

*691. **Shri Gulshan:**
Shri Shiv Charan Gupta:
Shri Shiv Charan Mathur:

Will the Minister of **Works and Housing** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that all the residents of the present temporary camps under the Jhuggi Jhopri Scheme in the Capital will be given alternative plots before 1967; and

(b) if so, whether Government have admitted the voters' list of 1961 bye-election in New Delhi as a solid proof for allotting 80 square yards plots?

The Minister of Works and Housing (Shri Mehr Chand Khanna): (a) No. Only those persons who were squatting on public and Government lands prior to July 1960, and are not Government servants or migratory labourers, will be allotted plots of 80 square yards or tenements as and when they become available.

(b) No.

श्री गुलशन : क्या यह सच है कि जिन झुग्गी झोंपड़ी वालों को 25 गज जमीन में बसाया जा रहा है—मैं ने उसको देखा है—वह इन्सान तो क्या एक परिवार के मुर्दों के लिए भी काफी नहीं है। क्या सरकार उनको 80 गज जमीन देने का विचार कर रही है ?

श्री मेहर चन्द खन्ना : ये दो किस्म के झुग्गी झोंपड़ी वाले हैं। एक तो वे हैं जो सन 1960 से पहले के बैठे हुए हैं और दूसरे वे हैं जो बाद में आए थे। पहले वालों को हमने 80 गज जमीन दी है, लेकिन बाद वालों को, उनका हक न भी मानते हुए, हमने उनको 25 गज जमीन दी है।

श्री गुलशन : जिन लोगों को सरकार ने 80 गज जमीन दी है और जो उस पर मकान बनाए हुए बैठे हैं, उनसे सरकार

किराया भी वसूल करती है और यह भी प्रतिबन्ध लगा दिया है कि जो मकान बने हैं उनको सरकार जब चाहे एक्वायर कर सकती है । यह प्रतिबन्ध तोड़ने के लिए सरकार कब तैयार होगी ?

श्री मेहर चन्द खन्ना : शुरू में हमने उनको मालिक बना कर गलती की । पहले उन लोगों ने मकान बनाए थे उनको बेच कर वे फिर स्कैवटर बन गए । हम ऐसा करने की इजाजत नहीं दे सकते । बाकी जो हमारी शरायत हैं वे लीज की हैं लम्बे अरसे के लिए । और हम उनको हर एक सहूलियत देने को तैयार हैं ।

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

Lady Hardinge Medical College and Hospital

***690. Shri Shiv Charan Gupta:** Will the Minister of **Health** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Workers' Union of Lady Hardinge Medical College and Hospital, New Delhi has given notice for going on strike;

(b) the nature of demands of the union;

(c) whether any of these demands has been examined by the management and are being considered favourably; and

(d) if not, the stepts Government propose to take to avert the strike?

The Minister of Health (Dr. Sushila Nayar): (a) to (d). A 30 days Strike Notice which has since expired was given on 15th February, 1965. Two demands set out in the Strike Notice were:

(i) to secure the implementation of the consequences and implications of the Award of the Industrial Tribunal published on 3rd December, 1964,

(ii) to press for a judicial enquiry by a retired High Court Judge into the cancellation of registration of this Union and registration of another Union instead.

The award of the Tribunal has been implemented already by the Management. The cancellation of the registration of the Union has been done by the Registrar of Trade Unions in the exercise of his functions and does not concern the Management.

Transactions between Orissa Government and Orissa Agents

***692. Shri Hari Vishnu Kamath:** Will the Minister of **Finance** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the special audit report on the transactions between the Orissa Government and "Orissa Agents" has been sent to the Governor of that State;

(b) if so, when; and

(c) whether the receipt of the said report has been acknowledged by the Governor or on his behalf?

The Minister of Planning (Shri B. R. Bhagat): (a) Government understand from the Comptroller and Auditor General that the results of the special audit referred to were communicated to the Government of Orissa on the 23rd July, 1964. Inspection Reports of this nature are, according to the normal practice not regarded as Audit Reports prepared for submission to the Governor under Article 151 (2) of the Constitution.

(b) and (c). Do not arise.

Shortage of water in Netaji Nagar, New Delhi

*693. **Shri K. C. Sharma:**
Shri A. V. Raghavan:
Shri Lakhmu Bhawani:
Shri Yashpal Singh:
Shri Kapur Singh:
Shri Onkar Lal Berwa:
Shri P. H. Bheel:
Shri Rameshwar Tantia: